संयुक्त राष्ट्र निकाय ने NHRC की मान्यता का स्थगन

स्रोत: द हिंदू

जिनेवा में स्थित और **संयुक्त राष्ट्र (UN)** से संबद्ध **ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (GANHRI)** ने लगातार दूसरे वर्ष **भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)** की मान्यता को स्थगित कर दिया है।

- यह निर्णय **मानवाधिकार परिषद** और कुछ **UNGA** निकायों में भारत के मतदान अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।
- **GANHRI** उन संस्थानों को **A-स्टेटस** देता है जो मानवाधिकारों की रक्षा में स्वतंत्रता और प्रभावशीलता के कुछ मानदंडों को पूरा करते हैं।
  - वर्ष 1999 में NHRI के लिये मान्यता प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से **NHRC** को A-स्टेटस से मान्यता प्राप्त है, जिसे उसने वर्ष 2006, 2011 और 2017 में स्थगन के बाद भी बरकरार रखा।
    - हालाँकि, वर्ष 2023 और 2024 में भारत के NHRC को लगातार दो वर्षों के लिये A-स्टेटस निलंबित कर दिया गया था।
- GANHRI की नवीनतम रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। हालाँकि, इसकी पिछली रिपोर्ट (वर्ष 2023 की रिपोर्ट) में स्थगन की सिफारिश के लिये कई कारण बताए गए थे। इनमें शामिल हैं:
  - **संरचना:** NHRC में सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव,
  - मानवाधिकार जाँच की निगरानी के लिये **पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति**
  - सदस्य पैनल में **लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व का अभाव**
  - NHRC "सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम" होने के लिये आवश्यक स्थितियाँ बनाने में भी विफल रहा है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/un-body-defers-nhrc-accreditation